

प्रधानमंत्री का आह्वान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' में अगस्त महीने को संकल्प का महीना बताते हुए हर नागरिक से भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लेने का जो आह्वान किया है उससे असहमत होने का कोई कारण नहीं है। इसी तरह उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की 75 वीं वर्षगांठ पर गंदगी, गरीबी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद एवं संप्रदायवाद भारत छोड़ो के संकल्प का जो आह्वान किया है, उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। आखिर ये सारी चुनौतियां हमारे देश के विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा हैं और भारत की छवि को दुनिया में खराब करती हैं। जब तक समाज का संकल्प और साथ नहीं होगा कोई सरकार इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक नहीं निपट सकती। प्रधानमंत्री ने इसके लिए आजादी के 75 वें वर्ष यानी 2022



तक सबको एक एकजुट होकर जी-जान से सफलता पाने के लिए पुरुषार्थ करने की भी अपील की है। वे ठीक ही कहते हैं कि अगर सवा सौ करोड़ देशवासी 9 अगस्त क्रांति दिवस को याद करके 15 अगस्त को संकल्प करें, तो जैसे 1942 से 1947 के पांच साल आजादी के लिए निर्णायक बन गए, उसी तरह ये पांच साल 2017 से 2022 भारत के भविष्य के लिए भी निर्णायक बन सकते

हैं। इस आह्वान और अपील का क्या असर होगा अभी कहना कठिन है, लेकिन देश के नेता के नाते उनका यह प्रयास उचित ही माना जाएगा। हम यहां निराशाजनक बात नहीं करना चाहते किंतु यहां यह प्रश्न भी पैदा होता है कि समाज के आम लोगों में ऐसे संकल्प कर भारत निर्माण के लिए काम करने का वैसा उद्यम भाव जैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं, कैसे पैदा होगा? एक मन की बात से तो यह संभव हो नहीं सकता। दुर्भाग्य से राजनीति और सत्ता इस समय सर्वोपरि हो गई हैं। जब तक इन दो स्तरों से संकल्प और पुरुषार्थ नहीं दिखेगा समाज के स्तर पर यह उतर नहीं सकता। क्या भारतीय राजनीति इस दिशा में सक्रिय दिख रही है? समग्र राजनीति की दशा वर्तमान संसद के हंगामे से स्पष्ट है। तो ले देकर सत्ता यानी सरकारों के कंधे पर ही सारा दारोमदार आ जाता है। सरकारों में केंद्र एवं राज्य दोनों शामिल हैं। जो कुछ प्रधानमंत्री ने कहा है उसे सबसे पहले उनके मंत्रियों, उनकी पार्टी के सांसदों, विधायकों और नेताओं को चरितार्थ करके दिखाना होगा। इसके साथ राज्य सरकारों को भी आपसी मतभेद भुलाकर इस तरह का प्रयास करते दिखना होगा। ऐसा अगर हुआ तो देश निश्चय ही उनके साथ उठ खड़ा होगा।